

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

आदेश

विभागीय पत्रांक— 695 दिनांक— 07.11.2006 द्वारा 'न्यू एरा हाई स्कूल, हनुमान नगर, कंकड़बाग पटना' के नाम से निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र में विद्यालय का परिवर्तित स्थलीय पता 'न्यू एरा हाई स्कूल, ज्ञानचक, पोस्ट— कोठिया, दीदारगंज, पटना' पढ़ा जाय।

इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें पूर्ववत्त रहेगे।

ए/
(दशरथ राम)
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापांक—10/न 4-50/2011... ५.३२ पटना, दिनांक 30/06/2011
प्रतिलिपि : अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र 2 कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली—110092 / जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/प्राचार्य, न्यू एरा हाई स्कूल, ज्ञानचक, पोस्ट— कोठिया, दीदारगंज, पटना' को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.6.11

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा

प्रक्रम - 10 / नं 4-37 / 2004 मा०..... / -

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना

प्रेषक,

श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

संवाद

श्री अशोक गांगुली.

अध्यात्म

जन्मदाता,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्युनिटी सेंटर
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक

विषय:- न्यू एरा हाई स्कूल, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना को अनापत्ति प्रभाण पत्र के संबंध में।

महाशय

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि विभागीय आधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार रिप्टिंग निम्नवत् के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार रिप्टिंग निम्नवत् है:-

- विद्यालय का संचालन निर्बंधित निकाय "न्यू एरा सोशल डेवलपमेंट वेलफेर सोसाइटी" के द्वारा किया जा रहा है। शपथ पत्र के द्वारा यह सूचना दी गयी है कि निकाय में किसी का स्वामित्व नहीं है और निकाय के सभी सदस्यों के बीच पारिवारिक संबंध नहीं है। निकाय के सदस्यों की सूची दी गयी है सदस्यों के पेशे के संबंध में सूचना नहीं दी गयी है। विभागीय अधिसूचना के अनुसार निकाय के सदस्यों के पेशे के वास्तविक जानकारी आवश्यक है। केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के अनुरूप शासी निकाय के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर ही अग्रेतर कार्रवाई करना चाहेगा।
 - विद्यालय के द्वारा किसी निर्बंधित सोसाइटी/न्यास के फेन्चाईजी का उपयोग तथा किसी अन्य विद्यालय के brand name का उपयोग नहीं करने का भी दावा किया गया है।
 - विद्यालय के द्वारा सूचना दी गयी है कि विद्यालय की पास अपनी भूमि 30 वर्षों के लीज पर जानीपुर फुलवारीशरीफ, पटना में है। तत्काल विद्यालय हनुमान नगर, कंकड़बाग में संचालित है। उक्त रथत पर विद्यालय ने 100 वर्षों के लीज पर भवन लिया है। भवन में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी है। निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय का संचालन उसके द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप निर्मित भवन एवं उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं के साथ हो रहा है।
 - विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित 27 शिक्षक हैं, जिनमें 4 प्रशिक्षित हैं। सभी शिक्षकों की योग्यता NCTE के निर्धारित मानक के अनुरूप बताया गया है। लेकिन विद्यालय में अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति से उत्तर सूचना विरोधगती हो जाती है; शिक्षकों दी गियुक्ति के रान्दर्भ में पिण्डापन यी प्रति दी गयी है। परन्तु ऐसे अभिलेख अथवा साक्ष्य उपरस्थापित नहीं किये गये हैं जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति की प्रक्रिया में पूरे नियमों का अनुपालन करते हुए पूर्णतः पारदर्शिता के साथ वर्तुनिष्ठ ढंग से शिक्षकों का चयन किया गया हो। केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जॉचोपरान्त यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षकों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया रो रामाचार पर में विज्ञापन के माध्यम से नहीं जाती है।
 - विद्यालय के द्वारा हिन्दी विषय पढ़ाने का दावा किया गया है।
 - विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा, अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक करने की सूचना दी गयी है। आवेदन के साथ कतिपय वर्षों के लेखा का अंकेक्षण की विधरणी भी उपरस्थापित की गयी है।
 - विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अंपेक्षित शर्तें स्वीकार हैं। लेकिन शर्तों के अनुरूप जहाँ तक जिन वर्च्चों का नामांकन नहीं होगा उनसे लिया गया नियंत्रण शुल्क एवं आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि

वापस लौटाने के सन्दर्भ में यह कहा गया है कि यह निर्धारिति पर निर्भर करता है। अपेक्षित शत्तों के अनुसार

- (i) विद्यालय में क्षमता का 25% नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क जायेगा तथा उनसे ट्रॉफी शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसा बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग वलिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- रुपये प्रतिवर्ष होंगे।
- (ii) विद्यालय में नर्सरी/को०जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुलें तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी/को०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

3. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जॉच कर यह रुनिशित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर रांचालिंप है।

4. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालयों के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं आपेक्षित शत्तों का अनुपालन हो जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इनका उल्लंख प्रोस्पेंक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा।

5. शत्तों के उल्लंघन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

6. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एवं उपर वर्णित शत्तों के आधार पर न्यू एरा हाई स्कूल, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

7. विद्यालय से प्राप्त आवेदन दिनांक 17.07.06 की छायाप्रति संलग्न है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक - यथोक्त ।

ह०/-

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह),
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञायांक -

695

प्रतिलिपि - प्रावार्य, न्यू एरा हाई स्कूल, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक:- ७.11.०६

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह),
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

अधिसूचना

संख्या— 13 / न4—34 / 99-238 राज्य सरकार (मानव संसाधन विकास विभाग) के कार्यालय आदेश-संख्या-720 एवं 721 दिनांक 26.7.99 के द्वारा क्रमांक सी०वी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई०, नई दिल्ली से निजी विद्यालय के संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के शर्ते निर्धारित की गयी थी। विधान मंडल में निजी विद्यालयों के प्रबंधन तथा किया-कलाप में माननीय सदस्यों की अभिव्यक्ति और निजी विद्यालयों के संबंध में विधान सभा फी विशेष समिति के प्रतिवेदन के आलोक में राज्यक विद्यारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त कार्यालय आदेशों को निरस्त करते हुए निम्नलिखित नीतिगत शर्ते निर्धारित करने का निर्णय लिया है:-

अनिवार्य शर्तें

- विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अथवा ट्रस्टीशिप एक्ट के तहत नियंत्रित होना चाहिए। नियंत्रित सोसाईटी/न्यास में किसी व्यक्ति/परिवार का प्राप्ति नहीं होना चाहिए। इसके प्राप्ति स्वरूप विद्यालय प्रबंधन को सोसायटी/न्यास के प्रत्येक सदस्य का नाम, पूरा पता, व्यवसाय, टेलीफोन नं० तथा आपस में सभी सदस्यों के संबंध हैं, की सूचना सार्वजनिक करनी होगी।
- विद्यालय किसी अन्य नियंत्रित सोसायटी/न्यास के franchise के रूप में स्थापित नहीं होगी तथा विद्यालय किसी अन्य सोसायटी/ट्रस्ट/संरक्षण द्वारा संचालित विद्यालय के brand/नाम का उपयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा।
- विद्यालय के पास भूमि, भवन, कागरों की संरक्षण, उपस्कर, प्रयोगशाला, पुरतकालय आदि सी०वी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने हेतु निर्धारित शर्तों के अनुरूप होगा।
- शिक्षक योग्यता/प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यानन्द शिक्षा परिषद (NCTE) मापदंडों के अनुरूप होगा तथा उनकी नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाल कर विहित प्रक्रिया से किये जाने की अपेक्षा होगा।
- विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाया जायगा।
- विद्यालय द्वारा निर्धारित दृश्यमान शुल्क, अन्य प्रकार का शुल्क (fees/charges) वार्षिक लेखा, अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सब चालू होने के पूर्व सार्वजनिक किया जायगा, अर्थात उसे "सूचना पट पर" निकाला जायगा तथा शिक्षक-अभिभावकों की बैठक में प्रस्तुत किया जायगा।

अपेक्षित शर्तें

इसके अलावे निम्नलिखित शर्तें यद्यपि बाध्य नहीं होंगे, परन्तु राज्य तथा वर्चों के द्वितीय में सरकार अपेक्षा करेगी कि सी०वी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० विद्यालय उसे स्वीकार करें। इसके लिए रक्कूल प्रबंधकों की सहमति माँगी जायगी।

- विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस निवास करने वाले परिवार के वर्चों का निशुल्क किया जायगा तथा उनसे दृश्यमान शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायगा। ऐसे वर्चों की श्रेणी में अनुरूपिता जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पराष्ट्र्यक, विकलांग, वालिकाएँ तथा सागान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/-रु० प्रतिवर्ष होंगे।

8. नर्सरी, केंजी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन के लिए अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

9. विद्यालय में नर्सरी, केंजी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन पत्र निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जाय।

10. जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गयी नियंत्रण तथा आवेदन शुल्क (प्रोसेप्टस सहित) का ८० प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

अनापत्ति पत्र वापस लेने/संबंद्धन रद्द करने संबंधी

11. शर्तों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध शिकायतों की सम्पुष्टि के उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने तथा यथा आवश्यक संबंद्धन रद्द करने के लिए राज्य सरकार सी०बी०एस०सी०/आई०सी०एस०सी० को अनुशंसा भेज सकते हैं।

12. अगर विद्यालय प्रवंधन, प्राचार्य अथवा शिक्षक बच्चों के विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं जो अपराधिक प्रकृति के हैं तथा जिनसे बच्चों के मानवीय अधिकारों (Human Rights) का हनन होता है, तो ऐसी रिति में जॉचोपरांत संबंधित विद्यालयों का अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लिया जायेगा अथवा यथा आवश्यक संबंद्धन रद्द करने की अनुशंसा वी जायगी।

(अमरेन्द्र शुक्रलूप रिंह)
सरकार के आपर राज्य
मानव संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- 238

पटना, दिनांक ३ मार्च, ०६

प्रतिलिपि विभाग के सभी निदेशक/उप शिक्षा निदेशक/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/मंत्री, मानव संसाधन विभाग के आपर सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार क्रूर राज्य
मानव संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- 239

पटना, दिनांक ३ मार्च, ०६

प्रतिलिपि अध्यक्ष, सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली/सचिव, सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, आई०सी०एस०ई०, नई दिल्ली, को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपूर्णसचिव
मानव संसाधन विभाग।